भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति घोषणा के बाद की पत्रकार वार्ता का संशोधित प्रतिलेख- दिनांक: 1 अक्टूबर, 2025 (बुधवार)

भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिभागी:

श्री संजय मल्होत्रा - गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री एम. राजेश्वर राव - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री टी. रबी शंकर - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री स्वामिनाथन जे. - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
डॉ. पूनम गुप्ता - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री इंद्रनील भट्टाचार्य - कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
डॉ. अजीत जोशी - कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक

संचालक:

श्री पुनीत पंचोली - मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

पुनीत पंचोली:

नमस्कार। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी मौद्रिक नीति के पश्चात आयोजित इस पत्रकार वार्ता में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हमारे साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा; उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर, श्री स्वामिनाथन जे. और डॉ. पूनम गुप्ता उपस्थित हैं। हमारे साथ कार्यकारी निदेशक डॉ. अजीत जोशी और पहली बार श्री इंद्रनील भट्टाचार्य भी उपस्थित हैं। मैं भारतीय रिज़र्व बैंक के अपने अन्य सहयोगियों का भी स्वागत करता हूँ। यथापरंपरा, हम कुछ आवश्यक अनुदेश देंगे।

महोदय, मीडिया के लगभग 23 प्रतिभागी उपस्थित हैं। मैं मीडिया के प्रतिभागियों से अनुरोध करता हूँ कि कृपया केवल एक प्रश्न पूछें ताकि सभी को अवसर मिल सके। मैं सभी से यह भी अनुरोध करता हूँ कि जब वे प्रश्न पूछें तो अपना माइक्रोफोन चालू कर दें, ताकि इस प्रसारण को सुन रहे लोग स्पष्ट रूप से सुन सकें। और अपना प्रश्न पूरा करने के बाद कृपया इसे बंद कर दें। महोदय, आपकी अनुमति से, मैं अब नाम पुकारूंगा। मैं सीएनबीसी टीवी-18 की सुश्री लता वेंकटेश से पहला प्रश्न पूछने का अनुरोध करूंगा। लता, कृपया।

लता वेंकटेश, सीएनबीसी-टीवी18:

धन्यवाद, पुनीत। और धन्यवाद, गवर्नर महोदय, इस अवसर प्रदान करने के लिए। आपने अपने विवरण में कहा है कि मुद्रास्फीति में गिरावट ने विकास को और समर्थन देने के लिए अवसर प्रशस्त किए हैं। आपने 'सीमित' शब्द का प्रयोग नहीं किया है, जो पहले आप 'सीमित अवसर' कहते समय उपयोग किया करते थे। तो, क्या हम यह समझें कि एक से अधिक कटौती के लिए अवसर उपलब्ध है? और इसका प्रभाव क्या होगा? यदि आपके पास अवसर था, तो अभी क्यों नहीं? आप किस प्रभाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं? आपने यह भी कहा कि नीतिगत उपायों का संचरण व्यापक है। क्या आप बॉण्ड प्रतिफल में हुई गतिविधि से संतुष्ट हैं? ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वहां संचरण हुआ हो।

संजय मल्होत्रा:

हाँ, जैसा कि आपने ध्यान दिया है, इसमें परिवर्तन आया है। मेरा तात्पर्य है कि जून में हमारी पिछली बैठक के बाद से मुद्रास्फीति में काफ़ी कमी आई है, लगभग 1%, और इसने अवसर प्रशस्त किए हैं। साथ ही, जैसा कि आपने देखा है कि हालांकि विकास ने पहली तिमाही, तीसरी तिमाही, चौथी तिमाही और यहां तक कि अगले वर्ष भी हमारे अनुमानों को सकारात्मक रूप से आश्चर्यचकित किया है, फिर भी इसमें थोड़ा कमी करते हुए संशोधन किया गया है। और जैसा कि उल्लेख किया गया है, यह शुल्क के कारण है; 50% का शुल्क लागू हुआ है, जिसकी कुछ हद तक वस्तु एवं सेवा कर द्वारा पूर्ति की गई है।

ब्याज दरों में कटौती न करने का कारण, जैसा कि हमारे विवरण में भी दिया गया है, यह है कि यद्यपि मौद्रिक नीतिका संचारण विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा रहा है, फिर भी यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। और यह केवल मौद्रिक नीति का संचारण ही नहीं है; अन्य नीतियां भी हैं, उदाहरण के लिए, सरकार द्वारा लागू किए गए वस्तु एवं सेवा कर की दरें और माननीय प्रधानमंत्री तथा सरकार द्वारा घोषित कई अन्य नीतियां। ये आकार ले रही हैं और इनका प्रभाव अभी भी सामने आ रहा है। साथ ही, अभी भी काफी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। हम हर सप्ताह, हर दिन नए विकास देख रहे हैं और वहां से प्रतिक्रियाएं भी देख रहे हैं। इस मामले में अभी पूर्ण स्पष्टता नहीं आई है। इसलिए, मौद्रिक नीति समिति ने महसूस किया कि हमें विराम देना चाहिए।

जहां तक सरकारी बॉण्ड्स में संचारण का प्रश्न है, जैसकि आप जानते हैं, 6.86% के शिखर स्तर से लगभग 6.30% तक लगभग 46 आधार अंकों का अच्छा संचारण हुआ था। इसके बाद कुछ कठोरता देखी गई है। अतः इसका शुद्ध प्रभाव केवल लगभग 26

आधार अंकों का है, जो आज 6.59% है, यानी लगभग 30 आधार अंक। हां, 30 आधार अंकों से अधिक या लगभग 30 आधार अंकों का प्रभाव सरकारी बॉण्ड प्रतिफलों में देखा गया है। हम सतर्क हैं और हम यह देखेंगे कि अंततः मांग और आपूर्ति के संदर्भ में स्थिति कैसे रहती है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अर्थव्यवस्था की सभी आवश्यकताओं का समर्थन कैसे किया जाए।

लता वेंकटेश, सीएनबीसी टीवी18:
'सीमित' शब्द के बारे में बताएं। आपने यह शब्द क्यों छोड़ दिया?

संजय मल्होत्रा:
मैंने पहले ही उल्लेख किया कि मुद्रास्फीति हमारे पिछले अनुमान की तुलना में 1% कम हो गई है। अब यह 2.6% पर है, जबकि पहले यह अधिक थी। इसलिए यह 1% कम हुई है, और यही कारण है। साथ ही, जैसकि मैंनो बताया, वृद्धि दर में भी थोड़ा नीचे की ओर संशोधन किया गया है, जो मुख्य रूप से व्यापार से संबंधित कारकों, विशेषकर लागू हुए उच्चतर शुल्क के कारण है, जिस पर अभी भी वार्ताएं चल रही हैं और स्थिति अभी भी स्पष्ट हो रही है। लेकिन हमनो इसे ध्यान में लिया है।

लता वेंकटेश, सीएनबीसी टीवी18:
क्या कटौती के लिए अवसर है? क्या यह अवसर सीमित है?

संजय मल्होत्रा:
हमनो उसमें परिवर्तन किया है। और यही कारण है। वृद्धि और मुद्रास्फीति की बदलती गतिशीलता ही वह कारण है जिसके लिए हमनो भाषा में परिवर्तन किया है।

पुनीत पंचोली:
धन्यवाद, सर। अगले प्रश्न के लिए, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से श्री मयूर शेट्टी को आमंत्रित करता हूं। मयूर, कृपया।

मयूर शेट्टी, टाइम्स ऑफ इंडिया:
सर, पिछली मौद्रिक नीति के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका से काफी प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, शुल्क संबंधी सूचनाएं आई हैं, एच-1बी वीजा को लेकर चर्चा हुई है, और अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने भी भारत को 'ठीक' करने की आवश्यकता पर बात की है। आपनो वृद्धि के अनुमान में कुछ समायोजन किए हैं। इसका वित्तीय बाजारों पर ठीक क्या प्रभाव पड़ेगा? और क्या आपनो जिन जीएसटी सुधारों और

विनियमन मुक्त करने का उल्लेख किया, वे अमेरिका के प्रभाव को संतुलित करने के लिए पर्याप्त हैं?

संजय मल्होत्रा:
हमारा प्रयास यही है कि जो भी बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियां हों, हम उनका मुकाबला करें। हमारी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से घरेलू मांग पर आधारित है, इसलिए प्रभाव सीमित है। यह कुछ अन्य देशों की तुलना में उतना अधिक नहीं है, जैसकि मैंनो पहले भी उल्लेख किया था। सरकार के साथ-साथ रिजर्व बैंक भी राजकोषीय, मौद्रिक और अन्य नीतियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेंगे कि किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का मुकाबला किया जा सके।

साथ ही, जैसकि आप जानते हैं, वार्ताएं अभी भी चल रही हैं। सरकार अन्य साधनों पर विचार कर रही है और अन्य बाजारों को खोल रही है। यूके के साथ पहले ही एक व्यापार समझौता हो चुका है। ओमान, यूरोपीय संघ (EU) सहित कई अन्य देशों के साथ वार्ताएं चल रही हैं, जो हमारे निर्यातकों के लिए नए बाजार खोलेंगी। और समग्र रूप से, भारतीय वृद्धि काफी लचीली (resilient) रही है, और हमें पूर्ण आशा है कि हम मूल्य स्थिरता बनाए रखते हुए बहुत उच्च वृद्धि पथ पर बने रहेंगे।

पुनीत पंचोली:
धन्यवाद, सर। अगला प्रश्न मैं बिजनेस स्टैंडर्ड से श्री मनोजित साहा को देता हूँ। मनोजित, कृपया।

मनोजित साहा, बिजनेस स्टैंडर्ड:
धन्यवाद, गवर्नर महोदय। टिप्पणी यह है कि मुद्रास्फीति कम हो रही है, जबकि व्यापार से संबंधित अनिश्चितताओं के कारण बांड प्रतिफलों में नरमी आई है। मैं यह समझना चाहता हूँ कि क्या यह स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि आगे चलकर ब्याज दरों में संभावित कमी हो सकती है? क्या दरों में वृद्धि का विकल्प अब समाप्त हो गया है? तो, क्या नीतिगत रुख को 'निभावकारी' में बदलने पर कोई चर्चा हुई थी?

संजय मल्होत्रा:
हाँ, जैसा कि आपने पहले ही नोट किया है, इस पर चर्चा हुई थी। दो सदस्यों ने इसकी वकालत की। आपके पास मत नहीं है। यह अधिकतर अग्रिम मार्गदर्शन के बारे में है। मैं फिर से स्पष्ट करता हूँ। यह स्पष्टीकरण पहले की किसी नीति में भी दिया गया था। इसका चलनिधि से कोई लेना-देना नहीं है। यह केवल एक अग्रिम मार्गदर्शन के

उपाय के रूप में है कि भविष्य में दरें किस दिशा में जा सकती हैं। तो, दो सदस्यों, प्रोफेसर राम सिंह और डॉ. नागेश कुमार ने, 'निभावकारी' रुख अपनाते हुए अपना मार्गदर्शन दिया, जबकि अन्य सदस्यों ने इसे 'तटस्थ' ही बनाए रखा है।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। अगला प्रश्न हम मनीकंट्रोल से सुश्री हंसिनी को देते हैं। हंसिनी, कृपया।

हंसिनी कार्तिक, मनीकंट्रोल:

धन्यवाद। नमस्कार, गवर्नर महोदय। मैं स्थूल आर्थिक पहलुओं से थोड़ा और जोड़ना चाहूंगी। नीति भाषण में एक बात जिसने मेरा विशेष ध्यान आकर्षित किया, वह है निर्दिष्ट बड़े कार्पोरेट्स के लिए निर्धारित सीमाओं को हटा दिया जाना। 2016 में इसे लागू करने का एक कारण यह बताया गया था कि एक जीवंत बांड बाजार विकसित किया जाए और बैंकिंग क्षेत्र को कुछ हद तक जोखिम-मुक्त किया जाए। तो, अब जब हमने उस निर्णय को वापस ले लिया है, तो हमें इससे क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? क्या इसका मतलब यह है कि बड़े निगमों के लिए ऋण वृद्धि को फिर से बैंकों द्वारा संचालित या समर्थित किया जाना चाहिए? या बांड बाजार में जीवंतता लाने के सभी प्रयासों के बावजूद, वह अभी तक पटरी पर नहीं चढ़ पाया है? सर, हमें इस विशेष बदलाव को कैसे समझना चाहिए?

और उसी के संदर्भ में, इस विशेष भाषण में बैंकिंग क्षेत्र के पक्ष में कई अन्य बदलाव भी किए गए हैं। उदाहरण के लिए, अधिग्रहणों के लिए वित्तपोषण आदि। बैंकों के लिए कारोबार करने में आसानी हेतु दरवाजे खोलने और उनकी कई मांगों को पूरा करने के पीछे क्या तर्क था?

संजय मल्होत्रा:

एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं। सबसे पहले, मेरी समझ यह है कि 2016 की नीति अधिकतर जोखिम को कम करने और बैंकिंग प्रणाली के स्तर पर बड़े कार्पोरेट्स के जोखिम को सीमित करने के बारे में थी, न कि व्यक्तिगत बैंक के स्तर पर। बैंक के स्तर के संबंध में, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो 'बड़ा एक्सपोजर ढांचा' पहले से मौजूद था, वह वैसा ही बना हुआ है। व्यक्तिगत बैंक के स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुआ है; जो भी बड़ा एक्सपोजर ढांचा था, वह जारी रहेगा। बैंकिंग प्रणाली के स्तर पर, किसी भी उधारकर्ता के लिए जिसका 2019 के बाद ₹10,000 करोड़ या उससे अधिक का ऋण सीमा या एक्सपोजर था, इस सीमा को 2016 से 2019 तक क्रमिक रूप से 25% से घटाकर 15% और फिर 10% कर दिया गया था। अब इसे हटा दिया गया

है क्योंकि यह महसूस किया गया है कि 'बड़ा एक्सपोजर ढांचा' व्यक्तिगत बैंक के स्तर पर आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। और बैंकिंग प्रणाली के स्तर पर भी, यदि आवश्यकता हो, तो हमारे पास पहले से ही मैक्रोप्रूडेंशियल उपकरण मौजूद हैं जो उसका ध्यान रख सकते हैं।

तीसरा, आपने देखा होगा कि वर्षों में कुल बैंकिंग एक्सपोजर में कार्पोरेट्स की हिस्सेदारी वास्तव में कम हुई है। मेरे पास सटीक संख्याएं नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में यह लगभग 10% या उससे अधिक कम हुई है। तो, जोखिम उतने अधिक नहीं हैं। यही मुख्य कारण है कि हमने बैंकिंग प्रणाली के स्तर पर विशिष्ट उधारकर्ताओं के लिए इस बड़े एक्सपोजर ढांचे को हटाने का प्रस्ताव रखा है।

और फिर, कारोबार करने में आसानी से जुड़े कई अन्य उपाय भी हैं। मुझे लगता है कि हमने कुछ दिनों पहले घोषित किए गए लगभग पांच छोटे उपायों के ऊपर सात और उपाय घोषित किए हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। हमें अपने विनियमों को तर्कसंगत बनाने के लिए लगातार देखने की आवश्यकता है ताकि अर्थव्यवस्था की उत्पादक आवश्यकताओं को न्यूनतम अनुपालन बोझ और न्यूनतम लागत के साथ पूरा किया जा सके, और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि जहां कहीं भी विवेकपूर्ण उपायों की आवश्यकता हो, उनसे समझौता न किया जाए।

पुनीत पंचोली:
धन्यवाद, सर। अब मैं ईटी नाउ स्वदेश से श्री अनुराग शाह को उनका प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। श्री अनुराग, कृपया।

अनुराग शाह, ईटी नाउ स्वदेश:
धन्यवाद श्री पुनीत। सर, आपने अपने वक्तव्य की शुरुआत में और अंत में दोनों जगह जीएसटी सुधारों का उल्लेख किया है। सर, वृद्धि का जो लक्ष्य आपने संशोधित किया है, उसमें शुल्क का योगदान कितना है और जीएसटी सुधारों का योगदान कितना है? क्योंकि यह सुधार 22 सितंबर से शुरू हुआ है। तो भविष्य में वृद्धि के परिदृश्य में और बदलाव आ सकते हैं। और मुद्रास्फीति, जिसे आपने 3.1% से घटाकर 2.6% किया है–सरकार द्वारा घोषित जीएसटी सुधार और उससे पहले बजट में घोषित व्यक्तिगत आयकर में बदलाव के बाद, लोगों के पास काफी पैसा आएगा जो खपत में जाएगा। तो इसका मुद्रास्फीति पर कितना प्रभाव पड़ेगा? मैंने पिछली बार एक प्रश्न पूछा था, लेकिन उसे ठीक से नहीं पूछ पाया। तो यदि आप अनुमति दें, तो क्या मैं इसे बाद में पूछ सकता हूँ?

संजय मल्होत्रा:

सबसे पहले, जैसा आपने कहा, चाहे वह जीएसटी हो या 50% शुल्क, इन सभी के प्रभाव को हमने अपने सभी अनुमानों में 'आधार लाइन' के रूप में 50% शुल्क मानकर शामिल किया है। लेकिन जैसा कि वक्तव्य में कहा गया था, वृद्धि दर के संदर्भ में, 50% शुल्क और उसके साथ जुड़ी अनिश्चितता तथा वैश्विक मांग का दोहरा प्रभाव पड़ता है।

एक प्रभाव वैश्विक मांग पर है—केवल अमेरिका की मांग ही नहीं, बल्कि समग्र वैश्विक मांग में कमी आएगी। इसके परिणामस्वरूप, जैसा कि आप जानते हैं, 20 आधार अंक का प्रभाव पड़ा है। इससे पहले हमारा अनुमान 6.7% से 6.5% था, और अब 50% शुल्क का प्रभाव मुख्य रूप से अमेरिका को होने वाले प्रत्यक्ष निर्यातों पर है। यदि वर्तमान में चल रही वार्ताएं सकारात्मक परिणाम देती हैं, तो इसमें कमी आ सकती है। जीएसटी का प्रभाव इससे कम होगा, अतः यह पूर्ण रूप से समायोजित नहीं कर पाएगा। कुल मिलाकर, जैसा कि हमने कहा, 20 आधार अंकों की कमी हुई है और हमने इन सभी प्रभावों को अपने अनुमान में शामिल किया है। हालांकि, इस वर्ष के लिए कुल वृद्धि का अनुमान बढ़ाया गया है, क्योंकि पहले छह महीनों में आर्थिक गतिविधि अच्छी रही है और आंकड़े हमारे पास уже आ चुके हैं।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। यदि समय मिला, तो बाद में पूछ लीजिएगा। सभी को अवसर मिलना चाहिए। धन्यवाद, सर। अगला प्रश्न मैं रॉयटर्स से सुश्री स्वाति भट को देता हूँ।

स्वाति भट, रॉयटर्स:

धन्यवाद सर। पिछले दशक या उससे अधिक समय से आरबीआई का मुख्य ध्यान बैंकिंग क्षेत्र के जोखिमों को कम करने पर रहा है, लेकिन अब बड़े एक्सपोजर ढांचे को सहज बनाकर, बैंकों को अधिग्रहण के लिए वित्तपोषण, आईपीओ वित्तपोषण, और शेयरों में अधिक निवेश की अनुमति देकर—क्या आप किसी प्रकार संभावित जोखिमों को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं? मेरा मतलब है, हम इस सभी सहजीकरण के माध्यम से क्या हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? धन्यवाद।

संजय मल्होत्रा:

हमने बहुत ही संतुलित, नपा-तुला, सोच-समझकर और विचार-विमर्श के बाद ये उपाय किए हैं। हालांकि औपचारिक परामर्श से पहले भी हमने कई परामर्श किए हैं और आगे

भी सार्वजनिक परामर्श किया जाएगा। इन उपायों में दोनों पक्षों का ध्यान रखा गया है। कम से कम दो ऐसे उपाय हैं–ईसीएल (प्रत्याशित ऋण हानि) और क्रेडिट जोखिम से संबंधित पूंजी पर्याप्तता मानदंड – जो मैं यह नहीं कहूंगा कि उच्चतर अपेक्षाएं लगाते हैं, लेकिन ये बेहतर तरीके से लक्षित होंगे। जोखिमों के आधार पर, कुछ बैंकों को अधिक प्रावधान रखने और उच्चतर क्रेडिट बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है; यह अधिक सटीक रूप से लक्षित होगा। इसी तरह, क्रेडिट के प्रवाह को बढ़ाने और बैंकों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए हमने जो अन्य उपाय किए हैं, वे पूरी तरह से नए नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अधिग्रहण वित्त पहले से ही अवसंरचना कंपनियों के लिए अनुमत था, अब हमने इसे विस्तारित किया है। इसी प्रकार, शेयरों के बदले में ऋण या आईपीओ वित्तपोषण पहले से ही मौजूद था, लेकिन कई वर्षों से इसकी समीक्षा नहीं हुई थी। इसलिए इसका संशोधन होना स्वाभाविक है।

समग्र रूप से, इन सभी उपायों का उद्देश्य स्थिरता को बढ़ावा देना है, और साथ ही प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना और अर्थव्यवस्था की वृद्धि को प्रोत्साहित व बढ़ाना है। हम आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में भी ऐसे और उपाय करते रहेंगे।

एम. राजेश्वर राव:

सर, जैसा कि गवर्नर महोदय ने पहले ही उल्लेख किया है...

संजय मल्होत्रा:

चूंकि कई उपाय वास्तव में विनियमन प्रभाग (regulation division) से संबंधित हैं, इसलिए मैं उप गवर्नर श्री एम.आर.आर. (डीजी एमआरआर) से अनुरोध करूंगा कि...

एम. राजेश्वर राव:

मेरा मानना है कि अधिकांश उपाय अच्छी तरह से सोचे-समझे और नपे-तुले हैं। दूसरा, समय के साथ जोखिमों को संभालने की बैंकिंग प्रणाली की क्षमता में सुधार हुआ है। इसलिए, पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं। तीसरा, इनमें से अधिकांश उपायों में बैंकों और वित्तीय प्रणाली के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय पहले से ही निर्मित हैं।

विशेष रूप से शेयरों के बदले ऋण की बात करें, तो हालांकि सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है, लेकिन ध्यान दें कि ये सीमाएं अंतिम बार 1998 में संशोधित की गई थीं। इसलिए, यदि आप मुद्रास्फीति को भी ध्यान में रखें, तो यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं है। समग्र रूप से, मेरा मानना है कि यह उपायों का एक कैलिब्रेटेड सेट है और यह फिर से सार्वजनिक परामर्श के लिए आ रहा है।

इसलिए, हम फीडबैक लेंगे और यदि उचित रूप से आवश्यक हुआ, तो इसमें संशोधन करेंगे।

पुनीत पंचोली:
धन्यवाद, सर। अगला प्रश्न हम एनडीटीवी प्रॉफिट से श्री विश्वनाथ नायर को देंगे।

विश्वनाथ नायर, एनडीटीवी प्रॉफिट:
नमस्कार, गवर्नर महोदय। मैं आपके आरबीआई गवर्नर के रूप में दिए गए पहले भाषण की ओर वापस जाना चाहूंगा, जहाँ आपने विनियमन की लागत और विनियमन में आसानी के बारे में बात की थी। क्या आज के भाषण में आपके द्वारा सूचीबद्ध इन 22 दिशा-निर्देशों या संकेतों को उसी दिशा में एक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए? क्योंकि जबकि ईसीएल एक अत्यंत आवश्यक और काफी समय से लंबित ढांचा है जो अब आ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि कई अन्य उपाय बैंकों को वही दे रहे हैं जिसकी वे मांग कर रहे थे। उदाहरण के लिए, अधिग्रहण वित्तपोषण या कुछ अन्य मामले, जिनके बारे में बैंकों ने पिछले कुछ हफ्तों में काफी जोरदार ढंग से बात की है। क्या हमें इन कदमों को उसी नजरिए से देखना चाहिए?

संजय मल्होत्रा:
हाँ, देखिए, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है, आवश्यकताएं बदलती हैं, इसलिए कुछ भी समय में स्थिर नहीं रहना चाहिए। इसीलिए हमने पहले भी कहा था कि हम अपने विनियमों की लगातार समीक्षा करते रहेंगे। वास्तव में, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वित्तीय क्षेत्र स्थिरता और विकास परिषद में हमने यह निर्णय लिया है कि सभी वित्तीय क्षेत्र के विनियामक हर 5 से 7 वर्ष में प्रत्येक विनियम की समीक्षा करेंगे। इसलिए, जैसा कि आपने उल्लेख किया, यह एक सतत प्रक्रिया होगी। जो मामले हमारे सामने आए हैं, हमने उन्हें संशोधित करना उचित समझा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने पूरे विनियामक पारिस्थितिकी तंत्र की लगातार समीक्षा, पुनरीक्षण और सुधार करते रहें।

पुनीत पंचोली:
धन्यवाद, सर। अगला प्रश्न हम ब्लूमबर्ग से श्री अनूप रॉय को देंगे।

अनूप रॉय, ब्लूमबर्ग:
धन्यवाद, सर। सर, आपने नीति में प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ रुपया संदर्भ दर (rupee reference rate) के बारे में उल्लेख किया है। अब तक हमारे पास चार

मुद्राओं के लिए रुपया संदर्भ दर है, और अब इसका विस्तार किया जाएगा। तो, वे कौन सी मुद्राएं हैं? और यह भी जानना चाहूंगा कि आप कौन सा बेंचमार्क संदर्भ दर उपयोग करेंगे? क्या इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपये के व्यापार में भी वृद्धि होगी? मेरा आशय यह है कि पहले क्रॉस-करेंसी (जैसे भारतीय रुपया-अमरीकी डालर और फिर अमरीकी डालर-चायना युआन का उपयोग होता था। आप इसे कैसे तय करेंगे?

टी. रबी शंकर:
हाँ, मेरा मानना है कि उद्देश्य दरों को प्राप्त करने के लिए परस्पर विनिमय की जाने वाली मुद्राओं के उपयोग को कम से कम करना है। इससे हमारी मुद्रा के साथ-साथ अन्य मुद्रा को भी लाभ होगा। वर्तमान में हम कुछ मुद्राओं पर विचार कर रहे हैं। हम इंडोनेशियाई रुपियाह को एक मुद्रा के रूप में देख रहे हैं, और दूसरे के लिए यूएई दिरहम को देख रहे हैं, लेकिन कुछ अन्य भी हैं। हम धीरे-धीरे इन्हें शामिल करते रहेंगे। बेंचमार्क कैसे तय किया जाए, इस आपके प्रश्न के संबंध में, हमें यह देखना होगा। शुरुआत में बहुत सक्रिय लेन-देन नहीं हैं, इसलिए हमें देखना होगा। वित्तीय बाजार संचालन संस्थान लिमिटेड को यह पता लगाना होगा कि कुछ शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। यह एक ऐसा मामला है जहाँ पहले कीमत-निर्धारण और संदर्भ दिखाना होगा, और बाजार को वहां से आगे बढ़ना होगा। इसे ध्यान में रखते हुए, हमें यह कार्य करना होगा कि इन संदर्भ दरों के लिए हम कैसे पहुंचें और कौन से बेंचमार्क का उपयोग करें। धन्यवाद।

पुनीत पानचोली:
धन्यवाद, सर। अब मैं ज़ी बिजनेस से सुश्री एक्ता सूरी को उनका प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित करूंगा।

एकता सूरी, ज़ी बिजनेस:
नमस्कार सर। मेरा प्रश्न आम लोगों और उनकी जेब से संबंधित है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि पिछली नीति से लेकर इस नीति तक, 2-3 खबरें सुर्खियों में रही हैं। पहली यह है कि बैंकिंग क्षेत्र के अनुसार, जिस तरह से यूपीआई लेन-देन बढ़ रहे हैं, उससे हमारे बुनियादी ढांचे पर बोझ पड़ रहा है, लेकिन लागत अभी तक वसूल नहीं की जा रही है। तो, क्या आने वाले दिनों में बड़े यूपीआई लेन-देन पर कुछ शुल्क लगाया जाएगा? दूसरी खबर यह है कि बैंकिंग क्षेत्र का कहना है कि यदि घर गृह ऋण (home loan) में गिरवी है या सोना स्वर्ण ऋण में गिरवी है, तो स्मार्ट उपकरणों जैसे स्मार्टफोन के मामले में वसूली की कोई संभावना नहीं है। तो क्या इस स्थिति में बैंक

पुराने तरीकों पर वापस जा सकते हैं जहां यदि आप ईएमआई का भुगतान नहीं करते हैं, तो फोन लॉक हो जाता है?

इसके अलावा, जिस तरह से सेबी ने 'वैलिड हैंडल' लॉन्च किया है, जिससे यदि मैं किसी धोखेबाज को पैसा दे रहा हूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि यह धोखाधड़ी है और सेबी के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है। तो, क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें यदि मैं पैसा स्थानांतरित कर रहा हूं, तो मुझे पता चल जाए कि यह एक धोखाधड़ी वाला खाता है या मैं इसमें फंस रहा हूं?

संजय मल्होत्रा:
तीन प्रश्न हैं। पहला यह कि क्या यूपीआई पर कोई शुल्क लगाया जाने वाला है। हमारे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

दूसरा, आपने कहा कि यदि मोबाइल फोन खरीदने के लिए ऋण दिया गया है, तो क्या हम इसे लॉक करने की अनुमति दे सकते हैं या नहीं, जैसे कि ऑटो ऋण आदि के मामले में दिया जाता है। यह मामला अध्ययनाधीन है। हमें दोनों पक्षों से प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। हम इसका संज्ञान ले रहे हैं। हमारा प्रयास यह है कि हमारे उपभोक्ताओं के अधिकारों और डेटा गोपनीयता की रक्षा की जाए। उपभोक्ता हित और उनका कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है, और साथ ही हम यह भी देख रहे हैं कि ऋणदाताओं के हितों की रक्षा कैसे की जाए- यह मामला अभी भी अध्ययनाधीन है।

आपका तीसरा प्रश्न धोखाधड़ी के बारे में था, जो एक बहुत ही गंभीर मामला है, और हमने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। एक खाते से दूसरे खाते में धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से धन स्थानांतरण को रोकने का तरीका खोजना हमारा निरंतर प्रयास है। इसी संदर्भ में हमने आपको 'म्यूलहंटर' के बारे में बताया है, और इसी तरह हम अब एक अन्य प्रयोग कर रहे हैं; हमने इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया है। हम लेन-देन की शुरुआत में ही सभी जानकारी एकत्र करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं ताकि हम अपने उपभोक्ताओं को चेतावनी दे सकें कि यह जोखिम भरा लेन-देन है - इस लेन-देन को आगे न बढ़ाएं। हम इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं।

मैं अपने उप गवर्नर से इसी बात को अंग्रेजी में समझाने का अनुरोध करूंगा। और मोबाइल फोन से संबंधित आपके दूसरे प्रश्न के संबंध में, मैं उप गवर्नर एमआरआर से इसे अंग्रेजी में अनुवाद करने का अनुरोध करूंगा।

टी. रबी शंकर:

नहीं, मैं गवर्नर द्वारा कही गई बात का अनुवाद करने का प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन हां, मूल रूप से बात यही है। डिजिटल भुगतान खुफिया प्लेटफॉर्म-(डीपीआईपी) - आपको याद होगा कि आरबीआई ने एक समूह का गठन किया था और इसकी घोषणा की थी। हम अब इसे लागू कर रहे हैं। जैसा कि गवर्नर ने कहा, वास्तविक प्रोटोटाइप हमारे इनोवेशन हब द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसे संचालित करने के लिए एक संस्था स्थापित की जा रही है।

इस प्लेटफॉर्म के पीछे मूल विचार यह है कि आप उपलब्ध सभी स्रोतों से जानकारी एकत्र करें–ठगी खाते), दूरसंचार, भूगोल, कॉल कहां से आ रही है, और जो भी जानकारी उपलब्ध हो। आपके पास एक एआई सिस्टम है जिसे इस जानकारी पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। विचार यह है कि यह सिस्टम लेन-देन से पहले चेतावनी देगा कि यह लेन-देन जोखिम भरा है। अब, चेतावनी के आधार पर, ग्राहक को निर्णय लेना होगा, या बैंक को निर्णय लेना होगा। हमें उम्मीद है कि इसका सिस्टम में देखी जाने वाली धोखाधड़ियों की संख्या को कम करने के मामले में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि धोखाधड़ियों की संख्या अधिक है। धोखाधड़ियों की संख्या अच्छी तरह से नियंत्रण में है। यदि आप यूपीआई और अन्य माध्यमों में लेन-देन प्रति धोखाधड़ी की संख्या को देखें, तो वे काफी कम हैं, लेकिन ये सिस्टम उन लेन-देन को और भी कम करेंगे। धन्यवाद।

एम. राजेश्वर राव:

डिजिटल लॉकिंग का मुद्दा, जिसका मैंने संदर्भ दिया था। जैसा कि गवर्नर ने इंगित किया है, यह मुद्दा जांच के अधीन है। ग्राहक अधिकारों और आवश्यकताओं, डेटा गोपनीयता, और साथ ही लेनदारों की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने के मामले में दोनों पक्षों के पक्ष और विपक्ष हैं। हम इस मुद्दे की जांच कर रहे हैं। हम पक्ष और विपक्ष का मूल्यांकन करेंगे और फिर बाद में एक निर्णय लेंगे।

पुनीत पानचोली:

धन्यवाद, सर। अगला प्रश्न मैं इकोनॉमिक टाइम्स से सुश्र ीता मेहता से पूछूंगा। संगीता, कृपया।

संगीता मेहता, इकोनॉमिक टाइम्स:

धन्यवाद, सर। सर, मेरा प्रश्न कारोबार के स्वरूपों से संबंधित है। आप सभी ने दिशा-निर्देशों में शिथिलता लाई है और कहा है कि बैंकों के बोर्ड को निर्णय लेने का

विवेकाधिकार होगा। आरबीआई ने इन मानदंडों को शिथिल करने का निर्णय क्यों लिया? और सर, इसी संदर्भ में एक और बात, बड़े एक्सपोजर ढांचे के लिए आप कौन से विशिष्ट मैक्रो-प्रूडेंशियल उपकरण का उपयोग करेंगे?

संजय मल्होत्रा:
सबसे पहले, आप 'शिथिलता' शब्द का प्रयोग कर रही हैं। मुझे सबसे पहले यह स्पष्ट करने दें कि वह केवल एक मसौदा था। वह किसी अंतिम दिशा-निर्देश या निर्देश के प्रकार का नहीं था। दूसरी बात देखिए, हम सूक्ष्म प्रबंधन नहीं करना चाहते। हमारा मानना है कि बैंक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपना व्यवसाय कैसे संचालित करना चाहते हैं, इसके संबंध में एक सचेत, विचारित और संतुलित दृष्टिकोण अपनाएंगे। इसलिए, हमने इसे उन पर छोड़ दिया है। दूसरा प्रश्न था कि मैक्रो-प्रूडेंशियल उपकरण क्या होंगे? हमारे पास उनकी संख्या है, मैं इसे उप गवर्नर एमआरआर पर छोड़ता हूं।

एम. राजेश्वर राव:
हमारे पास कई उपकरण उपलब्ध हैं। हो सकता है कि हम सभी बैंकों से किसी एक इकाई के एक्सपोजर पर एक उच्चतम सीमा लगाने पर विचार करें, क्योंकि मुझे लगता है कि गवर्नर द्वारा उठाया गया मूल बिंदु 'संकेंद्रण जोखिम' था–सभी बैंकों का किसी एक इकाई पर सामूहिक एक्सपोजर। इसलिए, हम इसके लिए सीमाओं के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिस पर उचित समय पर, यदि आवश्यक हो, तो विचार किया जा सकता है।

संजय मल्होत्रा:
और फिर हमारे पास पर्यवेक्षण भी है। यदि आवश्यक हो, तो हम पर्यवेक्षणात्मक उपाय भी लागू कर सकते हैं।

संगीता मेहता, इकोनॉमिक टाइम्स:
लेकिन यह पहले मसौदा होगा?

संजय मल्होत्रा:
हाँ। (व्यापार के स्वरूप पर) यह अब अंतिम है।

एम. राजेश्वर राव:
कारोबार के स्वरूप अंतिम हैं।

संजय मल्होत्रा:
कारोबार के स्वरूप अंतिम हैं।

संगीता मेहता, इकोनॉमिक टाइम्स:
नहीं, बड़े ऋण...

एम. राजेश्वर राव:
वह एक मसौदा परिपत्र है, सर।

पुनीत पंचोली:
धन्यवाद, सर। अगला प्रश्न हम पीटीआई से श्री आशीष अगाशे को देंगे।

आशीष अगाशे, पीटीआई:
बहुत बहुत धन्यवाद, सर। विश्वनाथ और स्वाति के प्रश्नों के त्वरित अनुवर्तन कुछ प्रश्न। पहले यह धारणा थी कि वित्तीय स्थिरता तरह-तरह की चीजों पर आरबीआई के दृष्टिकोण को अग्रिम पंक्ति में रखती है। क्या अब हमें यह समझना चाहिए कि यह अधिक व्यावहारिक होने की ओर एक मोड़ है? और सर, दूसरा त्वरित प्रश्न। आप वर्तमान में इन प्रतिकूल मौसम की घटनाओं को कैसे देखते हैं? पिछली नीति के बाद से ऐसी घटनाएं अधिक हुई हैं। तो, आप इसे मुद्रास्फीति और विकास के दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं?

संजय मल्होत्रा:
मुझे नहीं लगता कि आपको इन उपायों को किसी प्रकार की शिथिलता के रूप में या वित्तीय स्थिरता से अपनी दृष्टि हटाने के रूप में देखना चाहिए। स्थिरता हमारे लिए सर्वोपरि है। चाहे वह मूल्य स्थिरता हो या वित्तीय स्थिरता, यह न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे देश के लिए सर्वोपरि है। यह बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आपके पास मूल्य स्थिरता नहीं है, तो उसके परिणाम होते हैं। इसी तरह, वित्तीय स्थिरता के मामले में, वित्तीय अस्थिरता का एक भी प्रकरण आपको कई वर्ष पीछे ले जा सकता है। इसलिए, हम सभी को इस बात का बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। साथ ही, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम किसी भी प्रकार से विकास में बाधा न डालें या हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति को सीमित न करें। इसलिए, वित्तीय स्थिरता और मूल्य स्थिरता भारतीय रिजर्व बैंक का प्राथमिक फोकस बना रहेगा, जैसा कि अन्य सभी केंद्रीय बैंकों के लिए भी है।

मौसम से संबंधित घटनाओं के संबंध में, हाँ, उनका विकास और मुद्रास्फीति दोनों पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। साथ ही, आइए यह भी ध्यान में रखें कि सरकार ने भी कई उपाय लागू किए हैं। अब आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन बहुत बेहतर है, और वे इनका बेहतर ढंग से सामना करने में सक्षम हैं। इसलिए, हमने देखा है कि वर्षों में, जैसा कि आपने उल्लेख किया, अधिक मौसम संबंधी घटनाओं के बावजूद, मुद्रास्फीति बहुत बेहतर रही है। यह पिछले 10 वर्षों में पहले के 10 वर्षों की तुलना में कम रही है। साथ ही, हम अपने बैंकिंग प्रणाली के स्वास्थ्य के लिए जो भी आवश्यक होगा, वह करेंगे ताकि वह किसी भी मौसम या जलवायु से संबंधित जोखिमों का ध्यान रख सके।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। अगला प्रश्न श्री अंकुर मिश्रा, ईटी नाउ से होगा। अंकुर, कृपया।

अंकुर मिश्रा, ईटी नाउ:

अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते, सर। मैं आपसे रुपये के अवमूल्यन के संबंध में पूछना चाहता हूं, जिसका उल्लेख आपने नीति में भी किया है कि आप यथा आवश्यक कदम उठाएंगे। मौद्रिक नीति रिपोर्ट में इस बार विनिमय दर का अनुमान 86 से 88 तक संशोधित किया गया है। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि क्या वर्तमान विनिमय दर आपके लिए सुविधाजनक है? इसके अलावा, एमपीआर के संदर्भ में, आपने मुद्रास्फीति के लिए 4.5% का अनुमान लगाया है। उस संदर्भ में, तटस्थ दरों को बनाए रखते हुए और यहाँ वास्तविक दरों की बात करें, तो वे अनुमान से कम हैं। आपके पास राहत देने की कितनी गुंजाइश है?

संजय मल्होत्रा:

क्या अनुमान से कम है?

अंकुर मिश्रा, ईटी नाउ:

वास्तविक दर। 4.5% वह अनुमान है जो एमपीआर में दिया गया है।

संजय मल्होत्रा:

ठीक है। तो, आपका पहला प्रश्न किस बारे में था?

अंकुर मिश्रा, ईटी नाउ:
रुपये के बारे में।

संजय मल्होत्रा:
देखिए, रुपये के संदर्भ में, आपने पूछा कि क्या हम इस दर से सहज हैं आदि। तो, हमारा स्पष्ट मत है कि हम किसी विशिष्ट स्तर या किसी मूल्य बैंड को लक्ष्य नहीं बनाते। हमारा प्रयास किसी भी अनुचित अस्थिरता का प्रबंधन करना रहा है, और हम ऐसा ही करते रहेंगे। जहाँ तक भविष्य में वास्तविक दर का प्रश्न है, आपका उल्लेख इस 4.5% के बारे में है, जो पहली तिमाही (ति1) के लिए है। इसमें कई कारक शामिल होते हैं, और केवल मुद्रास्फीति ही नहीं है जिसे हमें देखना है; हमें अपने समग्र मैक्रो और मौद्रिक नीति में विकास को भी देखना होता है। इस आधार पर, हमने नीतिगत रेपो दर को 5.5% पर और रुख को 'तटस्थ' बनाए रखा है।

अंकुर मिश्रा, ईटी नाउ:
धन्यवाद।

पुनीत पंचोली:
धन्यवाद, सर। अगला प्रश्न श्री महेश नायक, फाइनेंशियल एक्सप्रेस से होगा।

महेश नायक, फाइनेंशियल एक्सप्रेस:
धन्यवाद, सर। इन सभी उपायों को अपनाए जाने के बाद, क्या आप अभी भी देश में पूंजीगत व्यय में किसी सकारात्मक संकेत या 'ग्रीन शूट्स' को देख रहे हैं, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के अलावा बड़े कार्पोरेट्स के संदर्भ में?

संजय मल्होत्रा:
हमें पहली तिमाही (ति1) में अच्छे आंकड़े मिले हैं; वे काफी स्वस्थ रहे हैं। हम कई क्षेत्रों में अच्छी मांग देख रहे हैं। उदाहरण के लिए, सीमेंट, ऑटोमोबाइल और कई अन्य क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय के लिए अच्छी मांग देखी जा रही है। और समग्र रूप से, हमें विश्वास है कि आगे चलकर पूंजीगत व्यय, विशेष रूप से निजी पूंजीगत व्यय, में और तेजी आएगी।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। सर, अगला प्रश्न श्री आर्यन खन्ना, इन्फॉर्मिस्ट मीडिया से होगा। आर्यन, कृपया।

आर्यन खन्ना, इन्फॉर्मिस्ट मीडिया:

धन्यवाद, सर। यह प्रश्न संभव हो तो गवर्नर और डीजी गुप्ता, दोनों के लिए है। एमपीसी के संकल्प में कहा गया था कि एमपीसी दरों पर आगे की कार्रवाई के लिए पूर्ववर्ती कदमों के प्रभाव की प्रतीक्षा कर रहा था। अंततः, पूर्ववर्ती कार्यों का संचरण होगा। आने वाली कुछ तिमाहियों के लिए आपके विकास और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को देखते हुए - आपके विचार में दरों में कटौती करने से क्या रोकेगा, विशेष रूप से वास्तविक और सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद को ध्यान में रखते हुए? जून तिमाही के वास्तविक और नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों ने अर्थव्यवस्था की बहुत अलग तस्वीर पेश की है। धन्यवाद, सर।

पूनम गुप्ता:

जैसा कि आप जानते हैं, मौद्रिक नीति एक अग्रिम-दृष्टि वाली प्रतिक्रिया है। इसलिए, हालांकि जैसा आपने कहा कि पहली तिमाही के आंकड़े वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से अच्छे रहे हैं, लेकिन वर्ष की दूसरी छमाही में कुछ नरमी का अनुमान लगाया गया है। और मुद्रास्फीति के आंकड़े भी आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही सौम्य रहे हैं। तो, मुझे लगता है कि इन दोनों विकासों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि हमने विवरण में कहा था, कु गुंजाइश खुली है, लेकिन इसे घरेलू और वैश्विक स्तर पर हो रही अन्य सभी घटनाओं के संदर्भ में देखा जाना होगा। यह एक तेजी से विकसित होने वाली और बहुत ही लचीली स्थिति है। हां, पहली तिमाही के आंकड़े अच्छे रहे हैं, लेकिन वे केवल उन कई कारकों में से एक हैं जिन्हें हम मौद्रिक नीति की कार्रवाई के लिए विचार में लाते हैं। और यह एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन यह एक पिछले को देखने वाला कारक है। उस हद तक, गुंजाइश मौजूद है। लेकिन जैसा कि कहा गया है और सर द्वारा भी दोहराया गया है, दिसंबर में अगली कार्रवाई का निर्णय लेने से पहले कई अन्य बातों को ध्यान में रखा जाएगा।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, मैडम। अगला प्रश्न श्री लालतेंदु मिश्रा, 'द हिंदू' से होगा।

लालतेंदु मिश्रा, द हिंदू:

नमस्कार, गवर्नर। आपने मेरे प्रश्न का आंशिक उत्तर पहले ही दे दिया है जो मैं पूछने वाला था। यह भारतीय अर्थव्यवस्था पर टैरिफ (tariff) के प्रभाव के बारे में है। क्या आरबीआई या एमपीसी ने विभिन्न क्षेत्रों पर इसके प्रभाव का आकलन किया है? धन्यवाद, सर।

संजय मल्होत्रा:

हाँ, हमारे पास वह मानचित्र और विवरण मौजूद हैं। आपको ज्ञात है कि किन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा–रत्न और आभूषण, झींगा, वस्त्र और अब थोड़ी बहुत हद तक जेनेरिक ब्रांडेड फार्मा, जो बाद में शामिल हुआ है, और फुटवियर। ये वे प्राथमिक क्षेत्र हैं जिन पर प्रभाव पड़ेगा।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। अगला प्रश्न सुश्री सुबहाना शेख, 'द मिंट' से होगा।

सुबहाना शेख, द मिंट:

नमस्ते, सर। सर, मैं मौद्रिक नीति संचरण पर पहले प्रश्न पर वापस जाना चाहती थी। आपने कहा था कि प्रतिफल पर प्रभाव पड़ा है–वे 30 से 35 आधार अंक बढ़ गए हैं। अब, यह जून की मौद्रिक नीति के बाद से बढ़ा है और हमने मौद्रिक नीति संचरण पर कुछ बाधाएं देखी हैं। तो, क्या आरबीआई इस बात से चिंतित है कि बॉड चैनल के माध्यम से मौद्रिक नीति संचरण प्रभावित हो रहा है? अपने आकलन में, क्या आप ओएमओ या जी-सेक खरीद को वापस लाएंगे? बाजार को यह आश्वासन देने के लिए कि नीतिगत रेपो दर में समायोजन दीर्घकालिक दरों तक पहुंचेगा, आप किस प्रकार के संकेत देंगे?

संजय मल्होत्रा:

देखिए, मौद्रिक नीति संचरण के लिए हमारे पास जो प्राथमिक उपकरण है, वह नीतिगत रेपो दर है और परिचालन लक्ष्य, जो हमारी भारित औसत कॉल दर है, उसे नीतिगत रेपो दर के साथ संरेखित करना है। पिछले महीने, यह 5.46% पर थी। जैसा कि मैंने आपसे उल्लेख किया, सभी क्षेत्रों में व्यापक संचरण हुआ है–चाहे वह मनी मार्केट हो, बैंक ऋण हो, या यहां तक कि कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड में पांच वर्षीय एएए रेटेड बॉन्ड अपने शिखर से 50 आधार अंक नीचे आ गए हैं। इसी तरह, अन्य बॉन्डों के लिए भी। इसी प्रकार, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए भी। यह एक प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है, और हमें उम्मीद है कि अन्य क्षेत्रों में भी संचरण होगा। कृपया यह

भी ध्यान में रखें कि यहां तक कि 10 वर्षीय बॉन्ड में, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, यह लगभग 25-30 आधार अंक है। केवल मौद्रिक नीति के कारण, यह इससे भी अधिक, 60 आधार अंक तक कम हुआ था। उसके बाद कुछ घटनाएं घटी हैं।

दूसरी बात यह है कि 10 वर्षीय जी-सेक एक-के प्रति-एक की गति से आगे नहीं बढ़ेगी। इसे भी ध्यान में रखें। 25-30 आधार अंक, जबकि और अधिक की गुंजाइश है, और हमें लगता है कि यह नीचे की ओर जाना चाहिए, इस संबंध में कई उपायों पर विचार किया जा रहा है, जिसमें यह भी शामिल है कि प्राथमिक जी-सेक नीलामी कैसे आयोजित की जाएंगी। इन सरकारी प्रस्तावों की अवधि न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारों की भी, को लेकर हमें काफी विश्वास है कि मौद्रिक नीति संचरण पहले से ही काफी हद तक हो चुका है और भविष्य में भी जारी रहेगा।

पुनीत पंचोली:
धन्यवाद, सर। बाईं ओर से ही, श्री बेन, 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' से। बेन, कृपया।

बेन कोचुवीदन, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस:
नमस्ते, सर। एक शिकायत या फिर एक सुझाव है। आरबीआई के वक्तव्य और विज्ञप्ति इन दिनों बहुत देरी से और बहुत अधिक समूहों में आ रहे हैं। क्या इन्हें एक उचित समय पर नहीं दिया जा सकता; क्या हम इसमें बेहतर काम नहीं कर सकते? जैसे बैंकिंग, सात विनियामक परिवर्तन, यह रात 10:20 बजे आए। या अंतिम बुलेटिन रात 11:30 बजे या कुछ ऐसा आया, यह हमारी क्षमता से परे है कि हम इसका प्रबंधन करें।

संजय मल्होत्रा:
हम चौबीसो घंटे और सप्ताह के सातों दिन कार्य करते हैं। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, और हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि इन्हें जारी किया जाए। आप इन्हें किस समय जारी किए जाने की अपेक्षा करते हैं?

लता वेंकटेश, सीएनबीसी टीवी-18:
शाम 6 बजे के बाद ठीक रहेगा।

संजय मल्होत्रा:

ठीक है, शाम 6 बजे तक। हम सभी दस्तावेज़, मुख्य रूप प्रेस विज्ञप्तियाँ और विनियमों को शाम 6 बजे तक जारी करेंगे। और यदि कोई चीज़ शाम 6 बजे के बाद विलंबित होती है, तो उसे अगले दिन जारी किया जाएगा। ठीक है, यह उचित बात है।

बेन कोचुवीदन, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस:

महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि मैं जानता हूँ कि भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) विशिष्ट संस्थाओं के नाम नहीं लेता, यह विनियामक है। लेकिन यह टाटा संस के आवेदन के बारे में है, जो पिछले वर्ष अगस्त में उनके गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) लाइसेंस के पंजीकरण रद्द करने हेतु प्रस्तुत किया गया था।

संजय मल्होत्रा:

वैयक्तिक संस्थाएँ। हम वैयक्तिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद। महोदय, अगला प्रश्न 'द हिंदू बिज़नेस लाइन' से श्री पीयूष जी का होगा। पीयूष जी, कृपया।

पीयूष शुक्ल, द हिंदू बिज़नेस लाइन:

शुभ अपराह्न, महोदय और महानिदेशक महोदय। धन्यवाद पुनीत जी। महोदय, आपने लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे पर एक चर्चा पत्र जारी किया था। सार्वजनिक फीडबैक देने की अंतिम तिथि पिछले महीने बीत चुकी है। आपको किस प्रकार के सुझाव प्राप्त हुए हैं—क्या शीर्षक (headline) या मूल (core) मुद्रास्फीति के साथ बने रहना है, या बैंड को संकीर्ण करना है? और हमें इसकी अपेक्षा कब तक करनी चाहिए, क्योंकि इसे मार्च अगले वर्ष से लागू किया जाना प्रस्तावित है?

संजय मल्होत्रा:

किसके बारे में पूछ रहे हैं आप?

पीयूष शुक्ल, द हिंदू बिज़नेस लाइन:

लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के बारे में।

संजय मल्होत्रा:

ठीक है।

पीयूष शुक्ल, द हिंदू बिज़नेस लाइन:

देश में 2,000 से अधिक अलग से शहरी सहकारी बैंक हैं। हमने पिछले वर्ष देखा है कि इनमें से कुछ में अभिशासन संबंधी समस्याएं रही हैं, जिनके कारण भारी धोखाधड़ी हुई है और जमाकर्ताओं को नुकसान हुआ है। शहरी सहकारी बैंकों को नए लाइसेंस देने का तर्क क्या है? या क्या आपको लगता है कि अभी भी वित्तीय समावेशन हेतु पैठ बनाना शेष है? और बेन जी के प्रश्न के संदर्भ में एक अनुवर्ती प्रश्न यह है कि हम समझते हैं कि आप संस्थाओं पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन इसकी अंतिम तिथि कल थी। तो अब क्या होगा? अब वे अनुपालन में नहीं हैं। तो हम क्या दृष्टिकोण अपनाते हैं?

संजय मल्होत्रा:

तो, आपका पहला प्रश्न लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के संबंध में है। देखिए, वह एक चर्चा पत्र है। हमें विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए हैं और उन सुझावों के आधार पर, हम अब संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देंगे। और हम अपनी सिफारिशें सरकार को भेजेंगे। यह एक सार्वजनिक परामर्श था। हमने ऐसा सभी हितधारकों को अपने विचारों के निर्माण में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए किया।

हमारे विचार सरकार को संचारित किए जाएंगे। लेकिन हमें प्राप्त हुए सभी विचारों को ध्यान में रखा जाएगा। अंतिम निर्णय सरकार का होगा।

शहरी सहकारी बैंकों पर आपका दूसरा प्रश्न है। सबसे पहले, यह एक चर्चा पत्र है। जैसा कि मैंने कहा, 21 वर्ष हो गए हैं, समीक्षा की भावना के तहत, कई विकास हुए हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम में स्वयं कई क्षेत्रों, जिनमें अभिशासन भी शामिल है, को अब भारतीय रिज़र्व बैंक की निगरानी और विनियमन के अधीन लाया गया है, कई सकारात्मक विकास हुए हैं। इसके बाद, हालांकि, यह कि लाइसेंसिंग को फिर से खोला जाए या नहीं, और यदि हाँ, तो किन सुरक्षा उपायों के साथ, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे हम आप सभी के पास टिप्पणी और प्रतिक्रिया के लिए रखेंगे। और केवल इसके बाद ही, हम इस पर अपना दृष्टिकोण अपनाएंगे। धन्यवाद।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, महोदय। दाहिनी ओर से कुछ प्रश्न। हम श्री कृष्ण कौशिक को 'फाइनेंशियल टाइम्स' से बोलने का आमंत्रित करते हैं। कृष्ण, कृपया।

कृष्ण कौशिक, फाइनेंशियल टाइम्स:
धन्यवाद, महोदय। मेरा प्रश्न वही है जो पहले पूछा गया था। महोदय, टाटा संस के संदर्भ में, चूंकि अंतिम तिथि आ चुकी है और बीत गई है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि उन्हें अभी के लिए आईपीओ लाने के लिए कोई छूट प्राप्त हो गई है? मैं जानता हूं कि यह किसी एकल संस्था का प्रश्न नहीं है; यह एक नीतिगत प्रश्न है क्योंकि उन्होंने अभी तक आईपीओ नहीं लाया है, फिर भी अंतिम तिथि समाप्त हो गई है।

संजय मल्होत्रा:
देखिए, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, हम किसी विशिष्ट संस्था पर टिप्पणी नहीं करते हैं। किसी भी संस्था का पंजीकरण जब तक रद्द नहीं किया जाता, तब तक वह अपना व्यवसाय संचालित करती रहेगी।

पुनीत पंचोली:
धन्यवाद, महोदय। और अंत में, हम 'निकेई' से श्री सौम्यजीत साहा को बोलने का आमंत्रित करते हैं।

सौम्यजीत साहा, निकेई:
नमस्ते, गवर्नर महोदय। हम रुपए के विषय में चर्चा करना चाहते थे क्योंकि कुछ अधिक मंदीवादी (bearish) अर्थशास्त्रियों की भविष्यवाणी है कि आने वाले कुछ महीनों में इसमें और गिरावट आ सकती है। जब निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता की बात आती है तो इससे स्पष्ट रूप से कुछ लाभ मिलते हैं, लेकिन इसके साथ ही जनभावनाओं का पहलू भी है। यह अक्सर भावनात्मक या यहां तक कि राजनीतिकृत भी हो जाता है।

हम केवल यह समझना चाहते हैं कि रुपए में कमजोरी या किसी ऐसे ही उतार-चढ़ाव के प्रति जनभावनाओं को आरबीआई किस प्रकार देखता है। क्या यह प्रकार आपके विचारों या कार्यवाही के निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होता है? वहां जनभावनाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं?

संजय मल्होत्रा:
देखिए, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, हम किसी विशिष्ट स्तर या बैंड को लक्ष्य नहीं बनाते हैं। यदि कोई सार्वजनिक राय आदि है, तो हम मानते हैं कि वह रुपए की कीमतों में पहले से ही समाहित हो जाती है। लेकिन हम किसी बैंड को धकेलते या लक्ष्य नहीं बनाते हैं। हम केवल किसी भी अनुचित असामान्य अस्थिरता को हटाने या नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, हमारे

पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार हैं। इसके जनता की भावनाओं या भावनाओं को प्रभावित करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, महोदय। इसके साथ ही हम इस पत्रकार सम्मेलन को समाप्त करते हैं। महोदय, धन्यवाद और सभी प्रश्नों के उत्तर देने और इसे अत्यंत संवादात्मक बनाने के लिए शीर्ष प्रबंधन का धन्यवाद। मैं यहां उपस्थित सभी मीडिया प्रतिभागियों को धन्यवाद देता हूं और आप सभी को एक सुखद दिन की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।